15 साल में दो प्रेम विवाह, हर बार मिला दर्द: पहले से तलाक

नई दिल्ली । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में विवाद होने के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़िता कविता शर्मा (30) को नजदीकी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल कविता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने छानबीन के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी सोनू शर्मा की तलाश की जा रही है। पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है। उसके आधार पर भजनपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कविता शर्मा, सी-ब्लॉक भजनपुरा में अपने माता पिता के साथ रहती है।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 121 ● नई दिल्ली ● शनिवार 21 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

उन्नाव दुष्कर्म मामला: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई को हाईकोर्ट से झटका, अदालत ने आत्मसमर्पण करने को कहा

दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने जयदीप सेंगर को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ अंतरिम जमानत के विस्तार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पाया कि जुलाई 2024 में मिली अंतरिम जमानत अप्रैल 2025 में अंतिम बार बढ़ाई गई थी। इसके बाद पांच तारीखों पर भी कोई विस्तार आदेश नहीं आया। जयदीप के वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देकर रिहाई बढ़ाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, आप आत्मसमर्पण करें, फिर हम देखेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका पर विचार से पहले उसे आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले 17 फरवरी (मंगलवार) को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 20 फरवरी तक बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। जयदीप सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जयदीप सेंगर की तीन महीने की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका का कड़ा विरोध किया। सीबीआई के वकील ने आरोप लगाया कि जयदीप द्वारा प्रस्तुत प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल दस्तावेज नकली है। जयदीप ने ओरल कैंसर से पीड़ित होने का हवाला देते हुए जमानत विस्तार की मांग की थी। उनकी याचिका में कहा गया कि यह जानलेवा स्थिति है, जिसमें पुनरावृत्ति के क्लिनिकल संकेत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें निरंतर विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 3 जुलाई 2024 को दी गई अंतरिम जमानत केवल दो महीने के लिए थी और उसके बाद कोई अनिश्चितकालीन विस्तार का आदेश नहीं है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह जयदीप की स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करे। उच्च न्यायालय ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दोषियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपने पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की है। पीड़िता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि सेंगर को मिली 10 साल की सजा बढ़ाई जाए और मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इस मामले में सेंगर के अलावा बाकी सभी दोषी फिलहाल जमानत पर हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने की। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 2 मार्च तय की है। सीबीआई की तरफ से वकील अनुभा भारद्वाज ने कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, उसके बाद आगे सुनवाई हो। इससे पहले, जस्टिस प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मंजू जैन की पीठ ने जल्दी सुनवाई की मांग वाली अर्जी पर विचार करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के पास भेज दिया था। गौरतलब है कि सेंगर कस्टोडियल डेथ मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसे उम्रकैद की सजा मिली हुई है। दोनों मामलों में उसकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है। पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ केस में सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।

बिजनेस से लीडरशिप तक: एसआरसीसी कॉन्क्लेव ने विद्यार्थियों को दिखाई राह

नई दिल्ली , श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी वर्ष में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 का सफल समापन उत्कृष्टता केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि नीति, प्रगति और शांति के संतुलन से ही भविष्य का निर्माण संभव के संदेश के साथ हुआ। उत्कृष्टता की सदी... थीम के तहत तीन दिनों तक चले इस फ्लैगशिप इवेंट में देशभर के युवाओं ने बिजनेस, पॉलिसी, इनोवेशन और लीडरशिप पर मंथन किया और विचारों से भविष्य की रूपरेखा गढ़ी। एसआरसीसी के 100वें साल में आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम ने देशभर के हजारों छात्रों को बिजनेस, पॉलिसी, इनोवेशन और लीडरशिप की दुनिया से रूबरू कराया। कार्यक्रम में अमर उजाला कार्यक्रम ने मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में अपनी टीम वर्क, विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान और रणनीतिक योजना बनाने की क्षमता को परखा। विशेष रूप से प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग चैलेंज में छात्रों ने अपने नवाचार और व्यावसायिक समझ का प्रदर्शन किया, जबकि केस स्टडी और पॉलिसी फॉर्मूलेशन में उनके आलोचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता की परीक्षा हुई। कार्यक्रम में बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्री लीडर्स ने हिस्सा लिया और छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की। यह आयोजन छात्रों के लिए सीखने और नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर साबित हुआ, जिससे उन्हें वास्तविक उद्योग परिदृश्यों में काम करने का अनुभव मिला। साथ ही, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनुराग ठाकुर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन, फरसाई के विशेषज्ञ, गेमिंग क्रिएटर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स जैसे कई पावरफुल स्पीकर्स ने छात्रों को प्रेरित किया। इसके अलावा मनोरंजन के लिए कॉमेडियन, अभिनेता, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने छात्रों को तरोताजा किया। कॉन्क्लेव के आखिरी दिन एयर स्टाफ के चीफ अमर प्रीत सिंह ने बिजनेस में लीडरशिप, साहस, सतत प्रयास का पाठ पढ़ाया। फिक्स डर्मा की संस्थापक शैली मेहरोत्रा और निविया की मैनेजिंग डायरेक्टर गीतिका मेहता ने बिजनेस में महिला को सामना करने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। ग्रांट थॉर्नटन पैनल में स्टार्टअप, ट्रेडिंग, इंवेस्टमेंट और अन्य पहलुओं पर छात्रों को जागरूक किया।

दिल्ली सरकार का एक साल पूरा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड किया पेश

नई दिल्ली । दिल्ली की भाजपा सरकार ने आज अपने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों और प्रदेश के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'आज सरकार को एक साल पूरा हुआ है। शायद इसी समय हम इस सचिवालय में पहुंचे थे। आज की यह रिपोर्ट कार्ड हमारे एक वर्ष के तथ्य है। यह सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। हमने एक वर्ष में दिल्ली को ठहराव की ओर ले जाने की कोशिश की है। हमने कागज कम और काम ज्यादा के पैटर्न को फॉलो किया। हमने अपनी पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना पर काम किया था। हमने 10 लाख का हेल्थ कवर दिया। हमने अटल कैंटीन को इस विजन के साथ शुरू किया ताकि कोई भूखा न सोए। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन शुरू की गई है।' सीएम ने बताया, 'पिछली कैबिनेट बैठक में हमने आयुष्मान योजना को लागू किया। इस एक वर्ष में हेल्थ कवर के लिए 7 लाख लोग पंजीकृत हुए और 30,000 से अधिक लोगों ने आयुष्मान और वय वंदना योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त किया। आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन संचालित हो रही हैं, जहां 5 रुपये में गरीबों, श्रमिकों और मजदूरों को सम्मानजनक तरीके से भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

झुग्गीवासियों के लिए हमने 700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, ताकि झुग्गियों में भी नाली, खड़ंजा, पार्क, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।'

दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक को बदमाशों ने मारी गोली, प्रॉपर्टी विवाद में किया हमला

नई दिल्ली । पुलिस ने हत्या का प्रयास का केस कर हमलावरों की की तलाश कर रही है। पीड़ित के बेटे ने अपने एक रिश्तेदार पर प्रॉपर्टी विवाद के लेकर गोली मारने का आरोप लगाया है। मुंडका के बक्करवाला इलाके में बृहस्पतिवार दोपहर प्रॉपर्टी विवाद में दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक 80 साल के रिशाल सिंह को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावरों ने उनपर पांच छह राउंड गोली चलाई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से पुलिस ने परिवार वालों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने हत्या का प्रयास का केस कर हमलावरों की की तलाश कर रही है। पीड़ित के बेटे ने अपने एक रिश्तेदार पर प्रॉपर्टी विवाद के लेकर गोली मारने का आरोप लगाया है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि 19 फरवरी की दोपहर करीब 1.15 बजे पुलिस को बक्करवाला इलाके से एक शख्स को गोली मारने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को 80 साल के रिशाल सिंह घायल अवस्था में मिले। जिसे पुलिस ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से परिवार वालों ने उन्हें राठी अस्पताल में शिफ्ट करवाया। पीड़ित के पेट, बाएं कंधे, दाहिनी कोहनी और दाहिने पैर में गोलियां लगी है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जांच में पता चला कि घायल रिशाल सिंह दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे और 2006 में सेवानिवृत हुए थे। पीड़ित के बेटे ने आरोप लगाया कि उसका एक रिश्तेदार सागर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। वह साथी के साथ मौके पर आया और उनके पिता पर पांच से छह राउंड गोलियां चलाईं। उसने पुलिस को बताया कि एक प्लॉट को लेकर उनका विवाद चल रहा था। हाल ही में अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था। उसके बाद उस प्लॉट पर उसके पिता दीवार लगाने का काम कर रहे थे। मौके की छानबीन के दौरान पुलिस को करीब 10 खाली कारतूस मिले हैं। पुलिस ने बेटे के बयान पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस नामजद आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके ठिकाने पर दबिश दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करना पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने हाईकोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के हिंदी साइनेज को सर्वोच्च न्यायालय में बदलना आसान नहीं है। इसमें करीब 40 से 45 लाख रुपये का खर्च आएगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच के सामने डीएमआरसी के वकील ने कहा कि केवल स्टेशन पर लगे बोर्ड ही नहीं, बल्कि रूट मैप, मोबाइल ऐप और अन्य सूचनात्मक सामग्री में भी बदलाव करना पड़ेगा। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वकील ने यह भी कहा कि अगर एक स्टेशन का नाम बदला जाता है, तो अन्य स्टेशनों के लिए भी इसी तरह की मांगें उठ सकती हैं। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। अदालत ने कहा कि भविष्य में और याचिकाएं आने की संभावना इस मामले का विरोध करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने डीएमआरसी को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह सुनवाई उमेश शर्मा की जनहित याचिका पर हो रही है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेशन का हिंदी नाम देवनागरी में सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अन्य स्टेशनों सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का हिंदी नाम केंद्रीय सचिवालय लिखा गया है। उन्होंने आधिकारिक भाषा कानून का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में साइनेज और नेम प्लेट अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में होने चाहिए .

पलवल के छांयसा गांव में पेयजल आपूर्ति के छह सैंपल हुए फेल, पानी में मिला जानलेवा बैक्टीरिया

फरीदाबाद । पलवल के छांयसा गांव में पेयजल आपूर्ति के छह सैंपल फेल पाए गए हैं। छह विभिन्न घरों से लिए गए इन सैंपलों में ई-कोलाई बैक्टीरिया पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहीं, गांव के छह घरों के कूंडे (पानी जमा करने के लिए जमीन में बने टैंक) में भी बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। 110 घरों में से लिए गए सैंपलों में से 57 में क्लोरीन भी कम मिला। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। विभाग के अनुसार, लोगों के बीमार होने के केस बढ़ने पर विभाग ने गांव में 386 सैंपल लिए थे। इनमें से बैक्ट्रोलोजिकल जांच के लिए 176 सैंपल भेजे गए। 76 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें 9 प्रतिशत में बैक्टीरिया मिला है। अभी 210 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे नहीं गए। जनस्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरवार को सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि इस रिपोर्ट में दूषित पानी को मौत का कारण नहीं माना गया। विभाग ने गांव में बीमारी से केवल सात मौतें होने की ही पुष्टि की है।

शुक्रवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में विपक्ष इस मामले में सरकार की घेराबंदी कर सकता है। पंचकूला स्थित जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग मुख्यालय ने इसीलिए वीरवार को ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी है। बैक्ट्रोलोजिकल टेस्ट के दौरान घरों में पानी आपूर्ति वाले सभी सैंपल लिए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि घरों तक पानी में बैक्टीरिया का मिश्रण तो नहीं हो रहा। ओटी टेस्ट में केमिकल की कुछ बूंदें डालकर यह देखा जाता है कि पानी से कोलीफार्म बैक्टीरिया खत्म करने के लिए क्लोरीन है कि नहीं। इसी तरह से अमोनिया, हेवी मेटल के टेस्ट में पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति मानकों पर खरी उतर रही है कि यह भी देखा जाता है। 176 में से शेष 100 सैंपलों की बैक्ट्रोलोजिकल रिपोर्ट लैब से आना शेष है। विभाग ने जो पानी की आपूर्ति हो रही है, उसके भी अमोनिया टेस्ट के 14 व हेवी मेटल के छह सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है।

ट्रेड यूनियनवाद का बदलता चेहरा

12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाया गया 'भारत बंद' संगठित श्रम की स्थायी ताकत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी बंद के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में, इस दिन ने यह दिखाया कि राष्ट्रीय प्रभाव कितना कम हो गया है। यूनियन नेताओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी का दावा किया, लेकिन कई राज्यों से रिपोर्टों में अधिकांश शहरों में सामान्य व्यावसायिक गतिविधि, कई क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का संचालन और केवल छिटपुट औद्योगिक व्यवधानों का वर्णन किया गया। कुछ ही इलाकों को छोड़कर, जहां यूनियनों के घने राजनीतिक और संस्थागत नेटवर्क हैं, दैनिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। यह परिणाम कुछ गहरा दर्शाता है – भारत का श्रम बाजार लंबे समय से अनौपचारिकता से आकार लेता रहा है और यह पैटर्न आज भी मजबूती से बना हुआ है। कामगारों का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 85-90 प्रतिशत, अनौपचारिक रोजगार व्यवस्था में बना हुआ है, जिसमें औपचारिक फैक्टरी नौकरियों से जुड़ी सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता नहीं है। साथ ही, हाल के श्रम बल सर्वेक्षण दिखाते हैं कि अधिकांश रोजगार प्राप्त व्यक्ति स्व-रोजगार वाले हैं, न कि नियमित वेतनभोगी, जो पारंपरिक यूनियनकृत कार्यबल की सीमितता को रेखांकित करता है। काम के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र सेवाओं, छोटे उद्यमों, ठेका व्यवस्थाओं और प्लेटफॉर्म-आधारित गिग रोजगार में हैं। ऐसे परिदृश्य में, पारंपरिक यूनियन मॉडल, जो बड़े कार्यस्थलों और दीर्घकालिक सामूहिक सौदेबाजी पर आधारित है, कार्यबल के केवल सीमित हिस्से को ही छूता है। सामान्य नागरिकों के लिए, ऐसी हड़तालें अक्सर एकजुटता की बजाय असुविधा और आर्थिक नुकसान में बदल जाती हैं। यात्रियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, छोटे व्यवसाय एक दिन की कमाई खो देते हैं और आवश्यक सेवाएं विलंबित हो जाती हैं। दैनिक मजदूरों और ठेका कामगारों के लिए भागीदारी का मतलब आय खोना होता है। अस्पताल, परीक्षाएं और नियमित लेनदेन बाधित हो जाते हैं। बंद, जो कभी लोकतांत्रिक जुटाव का नाटकीय साधन माना जाता था, अब रोजमर्रा के जीवन में थोपी गई रुकावट के रूप में अधिक देखा जाता है। यूनियनों और व्यापक जनता के बीच बढ़ती खाई के कई कारक हैं। रोजगार संरचनाएं यूनियन रणनीतियों से कहीं अधिक तेजी से विकसित हुई हैं। अनौपचारिक और गिग कामगार पारंपरिक संगठन ढांचों में आसानी से फिट नहीं होते। यूनियन नेतृत्व अक्सर विरासती क्षेत्रों और सार्वजनिक उद्यमों में केंद्रित रहता है, जहां संस्थागत लाभ मजबूत है लेकिन प्रतिनिधित्व की चौड़ाई संकरी है। हड़ताल की मांगें अक्सर सुधारों का विरोध या निजीकरण का विरोध करने पर केंद्रित होती हैं, बिना विस्तृत या व्यवहार्य या प्रशासनिक रूप से विश्वसनीय विकल्पों के। यह प्रतिक्रियावादी रुख बदलाव के प्रतिरोध का आभास दे सकता है बजाय रचनात्मक जुड़ाव के। वैश्विक व्यापार पर्यावरण तेजी से तनावपूर्ण हो रहा है, संरक्षणवादी प्रवृत्तियां फिर से उभर रही हैं और आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं। फिर भी भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला पूरी की है और खुद को विनिर्माण और सेवाओं के लिए तेजी से विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। जब सीमा-पार वाणिज्य अधिक अनिश्चित हो रहा है, भारत की नई व्यापार साझेदारियां हासिल करने की क्षमता अवसर और जिम्मेदारी दोनों दर्शाती है। देश इस औद्योगिक मोड़ पर चूक नहीं सकता, चीन को 3 दशक पहले इसी तरह का अवसर पकड़कर विश्व का कारखाना बनते देखने के बाद, निरंतर सुधारों और वैश्विक एकीकरण के माध्यम से। जैसे-जैसे भारत मेक इन इंडिया जैसी पहल आगे बढ़ाता है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहरी एकीकरण की तलाश करता है, कामगार कल्याण, कौशल, उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न और अधिक केंद्रीय हो जाते हैं। लेकिन एक आधुनिक, वैश्विक रूप से जुड़ी अर्थव्यवस्था में वैधता गतिविधि रोकने की क्षमता पर कम और सुधारों को जिम्मेदारी से आकार देने की क्षमता पर अधिक निर्भर करती है। ट्रेड यूनियनों को अपनी नैतिक सत्ता मजबूत करने के लिए आर्थिक उदारीकरण से विस्तृत प्रस्तावों के साथ जुड़ना चाहिए, कौशल विकास, लाभों की पोर्टेबिलिटी, कार्यस्थल सुरक्षा और विवाद समाधान पर, बजाय अधिकतमवादी बंदों पर निर्भर रहने के। ट्रेड यूनियनों के सामने रणनीतिक विकल्प है। वे पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, आगे देखने वाली मुद्रा अपना सकते हैं और राष्ट्रीय विकास में भागीदार बन सकते हैं, कामगार गरिमा की रक्षा करते हुए। या वे सिकुड़ते समूहों को जुटाने वाले प्रतीकात्मक बंदों के साथ जारी रह सकते हैं।

पूर्ववर्ती मार्ग ही कामगार कल्याण को भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के साथ संरेखित करता है। और भारत की आर्थिक यात्रा के इस मोड़ पर, वह संरेखण वैकल्पिक नहीं, आवश्यक है। कमल मदोशेट्टी

क्या 2027 में भी आम आदमी पार्टी पर पंजाबियों को भरोसा रहेगा?

2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व पर बहुत भरोसा जताया और उसके उम्मीदवारों को रिकॉर्ड संख्या में जिताया। पंजाब के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब एक ही पार्टी के 92 उम्मीदवार, वह भी ऐसी पार्टी, जिसकी लीडरशिप को किसी भी तरह से परखा नहीं गया था, जीत कर विधायक बने। इस तरह पंजाब में 'आप' की सरकार बनी और लोगों को उम्मीद होने लगी कि जल्द ही उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी और 'आप' की गारंटी पूरी होने से उनकी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। क्योंकि 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 22 के चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को कई गारंटियां दी और कई वादे किए थे। 'आप' सरकार ने जल्द ही लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अपना वादा पूरा किया और दावा किया कि 'आप' सरकार की वजह से पंजाब के 80 प्रतिशत लोगों का बिजली बिल जीरो हो गया है। लेकिन बाकी गारंटियां और वादे, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देना, बेअदबी के मामलों में 24 घंटे में इंसाफ, 3 महीने में नशा खत्म करना, वी.आई.पी. कल्चर खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करके सरकारी खजाने में सालाना 34,000 करोड़ रुपए जमा करना, रेत माफिया को खत्म करके 20,00 करोड़ रुपए तथा शराब पॉलिसी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करके पंजाब की आर्थिक हालत सुधार कर पंजाब को कर्ज के जाल से बाहर निकालना, सेहत और शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 पर लाना, कानून व्यवस्था सुधारने और पंजाब में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाकर युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और विदेश जाने की जरूरत खत्म करने जैसे वादे किए गए थे। भगवंत मान सरकार इनमें से ज्यादातर गारंटियां और वादे पूरे करने में नाकाम रही, हालांकि युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में काफी हद तक सफल रही लेकिन विपक्ष यह भी सवाल उठाता है कि सरकार यह क्यों नहीं बताती कि इन 4 सालों में कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं। सरकार के ये आंकड़े जारी न करने की वजह से विपक्ष का दावा है कि रिटायरमेंट दर 5 से 9 प्रतिशत है और आरोप है कि 'आप' सरकार ने उतने युवाओं को नौकरी नहीं दी, जितने रिटायर हुए हैं। इन्हीं वजहों से 2 साल बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 'आप' को 22 के मुकाबले बहुत कम रिस्पॉन्स मिला। इन चुनावों में 'आप' का वोट शेयर 41 से घटकर करीब 26 प्रतिशत रह गया और पार्टी के सिर्फ 3 उम्मीदवार ही जीत पाए, जबकि 'आप' के 2 उम्मीदवार आजाद के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा, कुछ ही महीने बाद 2022 में भगवंत सिंह मान अपने ही चुनाव क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान से हार गए। इन चुनावों के नतीजों से सीख लेकर 'आप' ने आत्ममंथन शुरू किया और पार्टी के काम करने के तरीकों में भी बदलाव किए। उसने कई तरह के कैंपेन भी चलाए। इनमें पंजाब को एक मॉडल राज्य के तौर पर पेश करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर शिकंजा कसना, बुलडोजर चलाना, महिलाओं को 1000 रुपए समेत बाकी गारंटियां और वादे पूरे करने का भरोसा दिलाना, पार्टी में अनुशासन लाना और अब ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के अलावा और भी कई कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इसी भरोसे की वजह से पार्टी को पिछले दिनों हुए उपचुनाव और स्थानीय चुनावों में कामयाबी मिली लेकिन इन जीतों को विधानसभा चुनाव जीतने की गारंटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर पंजाब के पिछले राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि पंजाब के लोग भरोसा करने में तो माहिर होते हैं लेकिन जब उनके भरोसे पर थोड़ी-सी भी चोट लगती है, तो वे भरोसा छोड़ भी देते हैं, जिसके 2 हालिया उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला, अकाली-भाजपा सरकार का बदलना। हालांकि पंजाबियों को अकाली-भाजपा सरकार के किए गए विकास से कोई एतराज नहीं था लेकिन धार्मिक मामलों में की गई गलतियों और ड्रग्स नियंत्रण के मुद्दे पर पंजाबियों का विरोध झेलना पड़ा, जिसकी वजह से अकाली दल और भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह, कांग्रेस सरकार, जो ड्रग्स खत्म करने, किसानों का कर्ज माफ करने और विकास के वादे की वजह से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, उसे भी पंजाबियों ने 2022 में बाहर कर दिया। लेकिन 'आप' की सरकार इन तीनों पार्टियों से ज्यादा और बड़े वादे करके आगे आई थी। अब पंजाबी फिर से सोचने लगे हैं कि किस पार्टी ने पंजाबियों से किए वादे पूरे किए। इसलिए, अब 'आप' पर दी गई गारंटियों और वादे पूरे करने का बोझ दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अगर पंजाबियों की सोच ऐसी ही रही और 'आप' गारंटियां और वादे पूरे नहीं करती, तो पंजाबियों की सोच 'आप' के लिए चुनौती बन सकती है और पार्टी के लिए 27 के विधानसभा चुनाव में पंजाबियों का 22 वाला भरोसा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।

अगर पंजाबियों की सोच ऐसी ही रही और 'आप' गारंटियां और वादे पूरे नहीं करती, तो पंजाबियों की सोच 'आप' के लिए चुनौती बन सकती है और पार्टी के लिए 27 के विधानसभा चुनाव में पंजाबियों का 22 वाला भरोसा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।

सम्पादकीय...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'सरकारें लोगों को मुफ्त के तोहफों की बजाय' रोजगार देने पर फोकस करें!

जब भी चुनाव निकट आते हैं, राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए 'फ्रीबीज' (मुफ्त की रेवड़ियां) का पिटारा खोल देती हैं। इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने की थी और तब से यह क्रम देश में हर आने वाले चुनाव के साथ-साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस वर्ष 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 20, 23, 10 और 7 मई को तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का 15 जून को समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में अप्रैल में चुनाव करवाए जाने की संभावना है, जिसके कार्यक्रम की घोषणा मार्च के मध्य में की जाएगी। इस बीच विभिन्न राज्य सरकारों ने मतदाताओं के लिए लोक लुभावन घोषणाओं की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें 'लक्ष्मी भंडार योजना' के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि बढ़ाने तथा 'बांग्लार युवा साथी योजना' के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह भत्ता देना आदि शामिल हैं। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ ही समय पहले कुछ समुदायों के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना की घोषणा की है जिसे बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनी 'तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड' ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि इससे उस पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 'सूर्यकांत' की अगुवाई में जस्टिस 'जायमाल्या बागची' और जस्टिस 'विपुल एम. पंचोली' की बैंच ने 'फ्रीबीज' पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ''यदि सरकार लोगों को सुबह से शाम तक मुफ्त बिजली, भोजन और गैस देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? इस तरह तो काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। गरीबों की मदद करना समझ आता है, लेकिन उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में फर्क किए बिना सब को मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है।'' ''कुछ लोग शिक्षा या बुनियादी सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें सुविधा देना राज्य का कर्तव्य है लेकिन 'फ्रीबीज' उनकी जेब में जा रहे हैं जो पहले ही मजे कर रहे हैं। क्या इस पर सरकारों को ध्यान नहीं देना चाहिए?'' ''देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में होने पर भी विकास की उपेक्षा करके मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। सरकारें मुफ्त की सुविधाएं देती रहेंगी तो इनका खर्च कौन उठाएगा? अंततः 'फ्रीबीज' का बोझ करदाताओं पर ही पड़ेगा। अतः देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।'' ''हमें ऐसे राज्य की जानकारी है, जहां फ्री बिजली है, भले ही आप बड़े लैंडलार्ड हों। यह टैक्स का पैसा है। हम सिर्फ तमिलनाडु के बारे में ही बात नहीं कर रहे। हम यह पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन से ठीक पहले योजनाओं की घोषणा क्यों की जा रही है?'' इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह 'अंतिम मिनट पर बिजली सप्लाई योजना' की घोषणा के समय तथा इसके पीछे के वित्तीय तर्क के बारे में स्पष्टीकरण दे। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यों को लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा से पूर्व वित्तीय नियोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि राजस्व घाटा इस हद तक न बढ़ जाए कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास प्रभावित हो।

एक ग़ैरबराबरी का समझौता जो औपनिवेशिक दौर की याद दिलाता है

प्रभात पटनायक

हम अगर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विशिष्ट प्रावधानों को अलग भी रख दें, तब भी इस समझौते की दो ऐसी असामान्य विशेषताएं हैं, जो इस समझौते के उस प्रकार की एक ग़ैरबराबरी की संधि होने को दिखाती हैं, जिस तरह की संधियां साम्राज्यी ताकतें वैश्विक दक्षिण या पिछड़ी दुनिया के ऐसे देशों पर थोपा करती थीं, जिन पर वे सीधे-सीधे राज नहीं करती थीं। इनमें पहली तो यही व्यवस्था है कि जिन माल को पूरी तरह से ही इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है उन्हें छोड़ दिया जाए तो, जहां अमेरिका भारतीय मालों पर 18 फीसद आयात शुल्क लगाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अनुसार मोटे तौर पर भारत, अमेरिकी मालों पर शून्य आयात शुल्क लगाएगा। इस तरह का समझौता करना जो आधिकारिक रूप से टैरिफ की दरों में इस तरह के अंतर को संस्थागत रूप से स्थापित करता है, बहुत ही अजीबो-गरीब है। इसका अर्थ तो यही है कि अमेरिका तो 'पड़ौसी जाए भाड़ में' की नीति अपनाएगा, लेकिन जिस पड़ौसी को इस नीति के जरिए वास्तव में 'कंगाल' बनाया जा रहा होगा, वह वास्तव में अमेरिका के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर के, अपने साथ ऐसा किए जाने के लिए 'मंजूरी' दे रहा होगा। दूसरी असामान्य विशेषता, इस प्रावधान में है कि भारत को अगले पांच साल तक, हर साल कम से कम 100 अरब डालर के अमेरिकी माल खरीदने होंगे। एक ऐसा व्यापार समझौता जो इसका प्रावधान करता है कि किसी देश को, हर सूरत में दूसरे देश से कम से कम कितने मूल्य के माल खरीदने होंगे, मुक्त बाजार की समूची विचारधारा के ही खिलाफ जाता है, जो कि पूंजीपति वर्ग को इतनी प्यारी है। इस विचारधारा के अनुसार तो वास्तव में कितने मूल्य का व्यापार होगा, खरीददारों के चयनों से तय होगा। उन्हें सरकारों द्वारा थोपा नहीं जा सकता है और इसलिए ये सरकारों के फैसले नहीं हो सकते हैं। इसलिए, खरीद के इस वादे का एक समझौते में शामिल किया जाना, पूरी तरह से अजीबो-गरीब है। और इससे भी ज्यादा अजीब है यह तथ्य कि यह न्यूनतम आंकड़ा, इस समझौते के एक पक्ष के लिए तो तय किया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए तय ही नहीं किया गया है, जो साफ तौर पर इसे एक ग़ैरबराबरी की संधि बना देता है। इस तरह की ग़ैरबराबरी की संधि तो किसी देश द्वारा दूसरे देश पर थोपी ही जा सकती है। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार चाहे कुछ भी दिखावा क्यों न करे, अमेरिका ने उसकी बांहें मरोड़ कर उसे इस समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला ही मौका है जब हमारे स्वतंत्र देश की सरकार इतनी कायरता का प्रदर्शन कर रही है कि उसने, एक ऐसी ग़ैरबराबर संधि पर दस्तखत कर दिए हैं, जो औपनिवेशिक दौर की याद दिलाती है।

रूसी तेल का मुद्दा- मेहनतकशों पर चोट

इस ग़ैरबराबरी की संधि के दो सबसे स्वतःस्पष्ट निहितार्थ हैं। पहला, रूसी तेल की खरीद के संबंध में। और दूसरा, कृषि क्षेत्र के संबंध में। एक सवाल जो सबसे पहले उठता है वह तो यही है कि भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका से भारत के आयात, जो इस समय 40 अरब डालर के करीब पर हैं, आने वाले वर्ष में कम से कम 100 अरब डालर हो जाएं। जाहिर है कि सरकार इसकी तो उम्मीद कर नहीं कर रही हो सकती है कि भले ही अमेरिकी मालों पर टैरिफ घटाकर शून्य कर दिया जाए, तमाम तरह की अमेरिकी सेवाओं तथा मालों का आयात, कुछ ही महीनों में बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। जाहिर है कि वह इसी के भरोसे होगी कि रूसी तेल के आयात में कमी की जाएगी और उसकी जगह अमेरिकी तेल खरीदा जाएगा, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो आयात में ऐसी बढ़ोतरी को संभव बना सकती है। लेकिन, ऐसा करना न सिर्फ अमेरिकियों के उस फरमान को लागू करना होगा, जिसकी मांग अमेरिकी काफी अर्से से करते आ रहे थे, बल्कि यह हमारे देश के तेल आयात के बिल को बढ़ाने का भी काम करेगा और देश में मुद्रास्फीतिकारी दबावों को और बल देने का काम करेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी तेल, रूसी तेल के मुकाबले कम से कम 20 फीसद के करीब महंगा बैठेगा। औसतन भारत के कुल तेल आयात का एक-तिहाई रूस से आता है। बेशक, यह तब की बात है जब तक भाजपा-नीत सरकार ने रूस से तेल की खरीद में कटौती शुरू नहीं की थी, जैसी कटौती पिछले कुछ महीनों से जारी है। लेकिन, यह कटौती तो अपने आप में ही, इस व्यापार समझौते की पूर्व-भूमिका थी, ताकि इसके प्रभाव को अलग से देखकर नहीं बल्कि व्यापार समझौते के साथ जोड़कर ही देखा जाए। अब अगर हमारा तेल का कुल आयात 120 अरब डालर के करीब माना जाए, तो इस तरह रूसी तेल की जगह अमेरिकी तेल को अपनाने से, हमारे तेल आयात के बिल में करीब 8 अरब डालर की बढ़ोतरी हो जाएगी। यह तो उस औपनिवेशिक किस्म की 'निकासी' या ड्रेन का सिर्फ एक तत्व है, जिसे इस नये व्यापार समझौते के जरिए अमेरिका, भारत पर थोप रहा है। और यह 'निकासी' कोई भारतीय तेल की कंपनियों की जेब से नहीं आ रही होगी। ये कंपनियां तो इस बोझ को, घरेलू बाजार के लिए अपने मालों की बढ़ी हुई कीमतों के जरिए, सीधे-सीधे जनता के ऊपर डाल देंगी। इसका अर्थ होगा, अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीतिकारी धक्का लगना, जिसकी असली मार मेहनतकश जनता पर पड़ेगी क्योंकि उसकी रुपयों में जो आय होती है, वह किसी भी तरह से कीमतों के बढ़ने के साथ बंधी हुई नहीं है। इसलिए, रूसी तेल की जगह पर अमेरिकी तेल का लाया जाना, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ही मामला नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीय प्रश्न भी है।

किसानों की बर्बादी

जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, सरकार दावा कर रही है कि चूंकि चावल तथा गेहूं जैसे कुछ महत्वपूर्ण अनाजों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए इस समझौते का खेती पर असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन, जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने खुद कबूल किया है, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कबूल नहीं किया है, कृषि के क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के या डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। सेब, कपास, ट्री नट्स, ताजा तथा प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन का तेल और वाइन तथा स्प्रिट्स, इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इसके अलावा डीडीजी तथा लाल ज्वार जैसे पशु आहारों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों में करीब-करीब इजारेदारी की हैसियत दिलाने जा रहा है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे राज्यों पर इस सबकी खासतौर पर भारी मार पड़ने जा रही है। बेशक, यह दलील दी जाएगी कि देश में पशु आहार की तंगी है और इसलिए इसका आयात बढ़ना तो देश के लिए फायदे का ही होगा। लेकिन, अपनी तंगी के लिए आवश्यक मात्रा में आयात लाना एक बात है और इस तरह के आयात के लिए, वह भी जीरो टैरिफ पर, अपने पूरे के पूरे बाजार के ही दरवाजे खोल देना, बिल्कुल अलग ही बात है। इसी प्रकार, वाणिज्य मंत्री के इस इस दावे से कोई खास संतोष नहीं मिल सकता है कि भारत-अमेरिका समझौते में दुग्ध उत्पादों को तो बाहर ही रखा गया है, जबकि यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम के साथ हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों में तो दुग्ध क्षेत्र शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन इस समझौते के चलते अमेरिकी किसानों की आय में अरबों डालर की बढ़ोतरी की बातें कर रहा है, जबकि भारत सरकार देश की खेती के लिए इस समझौते के किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभावों से इंकार ही कर रही है। अगर अमेरिकी किसानों को भारत में बढ़ा हुआ बाजार हासिल होने जा रहा है, तो अनिवार्य रूप से इसका अर्थ यही है कि भारतीय किसानों को इस बाजार से धकिया कर बाहर किया जा रहा होगा। इसका इकलौता अपवाद होगा, पशु आहार जैसी लागत सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाले कुछ कृषि उत्पादों की तरह उभी की चित्त व्यवस्था से संचालित खरीददारी। लेकिन, इस तरह की खरीददारी तो इस समझौते के चलते भारत के लिए कृषि निर्यातों में कुल बढ़ोतरी का एक छोटा सा अंश भर होगी।

औपनिवेशिक दौर की प्रतिध्वनि

पुनः यहां भी हमें औपनिवेशिक दौर की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तब किसान तथा खेत मजदूर, अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक अतिक्रमण के बदतरीन शिकार हुए थे। इसीलिए, उपनिवेशविरोधी संघर्ष के बैनर पर अंकित नारों में सबसे ऊपर यही नारा अंकित था कि स्वतंत्र भारत में किसानों और मजदूरों को कभी भी ऐसी दुरवस्था का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन, स्वतंत्रता संघर्ष के इस वादे के साथ पूरी तरह विश्वासघात करते हुए, एक बार फिर उनके ऊपर वही मुश्किलें ढहायी जा रही हैं और हैरानी की बात नहीं है कि यह एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका भारत की आजादी की लड़ाई से कुछ भी लेना-देना ही नहीं था। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी आम तौर पर इसका दोष पूरी तरह से मोदी सरकार के ही सिर पर डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन, यह सतही समझ है। सरकारें और इसमें फासीवादी सरकारें भी आती हैं, खास वर्गों के ही हितों में काम करती हैं। और यह उल्लेखनीय है कि इस समझौते की खबर से, भारतीय शेयर बाजार में बड़ा भारी जोश पैदा हुआ है। भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग और वेतनभोगी तबके के ऊपर वाले हिस्से और पेशेवर लोग, अमेरिका के साथ इस तरह के गठजोड़ के पक्ष में हैं, भले ही यह देश के मेहनतकशों की कीमत पर किया जा रहा हो। भारतीय बड़े पूंजीपति वर्ग की वैश्विक बनने की तलाश को, अमेरिकी बाजार की उपलब्धता से बढ़ावा मिलता है, भले ही इसके लिए 18 फीसद टैरिफ ही क्यों नहीं चुकाना पड़ रहा हो। इसी प्रकार, वेतनभोगी वर्ग के ऊपर वाले हिस्से और पेशेवर लोग, अपने बच्चों को अमेरिका में सैटल होते देखना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा को ट्रंप के वैर-भाव से एक धक्का लगा था और अब उन्हें अपनी इस इच्छा के पूरा होने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। साम्राज्यवाद के सामने इस समर्पण के पीछे है, आजादी की लड़ाई के दौरान बने उपनिवेशविरोधी वर्गीय गठबंधन का दरकना, जिसका नतीजा यह हुआ है कि बड़ा पूंजीपति वर्ग और वेतनभोगियों का ऊपरी संस्तर तथा पेशेवर, अपने ही स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनतकश जनता के हितों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।

लग्जरी कारें चलाने वाले 'बिगड़ैल बच्चों' से निपटना

इस बार पिता को ध्यान देना पड़ा क्योंकि लड़के ने सड़क की गलत साइड पर गाड़ी चलाई और सीधे एक आती हुई कैब और एक टू-व्हीलर को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पलट गई। इस वजह से साहिल नाम के 23 साल के लड़के की मौत ने एक न्यूज चैनल का ध्यान खींचा, जिसने एक वीडियो हासिल किया, जिसमें पूरा मामला दिखाया गया था और उसे सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाया। चैनल ने कसम खाई है कि जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अब समय आ गया है कि अधिकारी समझें कि सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल करने वाले आम लोग भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, जितने अमीर और ताकतवर लोग, जिन्हें गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं लगती।

लगभग 1 साल पहले पुणे के मामले में, जो लड़का रैश ड्राइविंग के लिए जिम्मेदार था, वह एक टीनएजर था जो अपनी महिला साथियों को दिखावा कर रहा था, जो 'बिगड़ैल बच्चों' के साथ आम बात है। भारत भर के शहरों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें अमीर परिवारों के नौजवान, अपने माता-पिता या दादा-दादी के लाड़-प्यार में पले-बढ़े और ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद महंगी कारें चलाने की इजाजत पाले हुए हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में एक और आम बात यह है कि ये युवा लड़के और उनके दोस्त शराब के बार में पैसे उड़ाते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, जिससे हर तरफ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में अमीर और ताकतवर लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा है। जब वे कानून तोड़ते हैं, तो उनके माता-पिता उन 'बड़ों' को सजा देने की बजाय, नेताओं, वकीलों और अपने पैसे से गुनहगारों को बरी करवा देते हैं! इस तरह के हक की भावना और कानूनों के प्रति हमेशा बेइज्जती की भावना, जो आसानी से समझ आने वाले युवाओं में पैदा होती है, मजबूत हो जाती है। इससे निपटने के लिए सीनियर अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की जगह पर तुरंत जाने का काम सौंपा जाना चाहिए। पुलिस मैनुअल, जिसमें ए.एस.पी. या एस.डी.पी.ओ. (सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर) की ऐसी 'विजिट्स' को जरूरी बनाया गया था, अब उसमें उन कार एक्सीडेंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें अमीर परिवारों के कम उम्र के युवा शामिल हों या मीडिया या आम जनता द्वारा उनके शामिल होने का आरोप लगाया गया हो।

सीनियर सुपरवाइजिंग ऑफिसर को घटनास्थल पर जल्दी भेजने से लोकल पुलिस के पैसे के दम पर असर पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। कई परिवार दो नहीं, बल्कि 4 या उससे भी ज्यादा लग्जरी कारों की शान दिखाते हैं। उनके बच्चे इन कारों के ज्यादा दीवाने हैं और रोजमर्रा की बातचीत में खुलेआम इनकी कीमत बताते हैं। इससे उन्हें स्कूल और बाजार में अपने दोस्तों के साथ ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए 'बिगड़ैल बच्चे' गैराज में छाए रहते हैं। ड्राइवर अपने छोटे मालिकों को लाड़-प्यार करते हैं। वे उन्हें गाड़ी चलाना सिखाते हैं, भले ही कानूनी तौर पर वे उस उम्र तक नहीं पहुंचे, जहां कानून कहता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। कानपुर के तम्बाकू टाइकून के बेटे को टेलीविजन पर दो हट्टे-कट्टे आदमियों द्वारा ड्राइवर सीट से उठाते हुए देखा, जिन्हें टैलीविजन चैनल ने 'बाउंसर' बताया, लेकिन जो साफ तौर पर उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। आम लोग भी इस तमाशे के गवाह थे। फिर भी, टाइकून के वकील को लगा कि थोड़ी सी मदद से कहानी को आसानी से बदला जा सकता है! कम उम्र के लड़कों की वजह से सड़क पर बेगुनाह लोगों की मौत की घटना से तुरंत निपटना होगा। इसमें प्यार करने वाले माता-पिता की लापरवाही शामिल है, जिन्हें अपने बच्चों को उनके पिता की दौलत पर पैसे लुटाने की बजाय अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। ड्राइवर तो वह चुना हुआ रूप है, जिसमें से बलि का बकरा ढूंढा जाता है।

अगर उन्हें जेल जाना पड़े तो बड़े लोग उनका और उनके परिवारों का ख्याल रखते हैं। बेगुनाह ड्राइवरों को सजा से बचाने के लिए सरकार को इस खतरे को रोकने के लिए कुछ नया सोचना होगा। एक तरीका जो दिमाग में आता है, वह है सजाओं की सूची में जेल या जुर्माने के अलावा एक और क्लॉज जोड़ना। यह सजा, जिसे मैजिस्ट्रेट या जज को लगाने की इजाजत होनी चाहिए, वह है माता-पिता को ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट में एक महीने या उससे भी ज्यादा समय के लिए वर्कशॉप में शामिल होने के लिए 'इनवाइट' करना, जहां देश के कानूनों का सम्मान करना सिखाया जाता है। कम उम्र के उल्लंघनकर्ताओं को अपने माता-पिता के साथ वर्कशॉप में शामिल होना चाहिए। जब मैं यह आर्टिकल लिख रहा था, तो मैंने एक न्यूज चैनल पर सुना कि दिल्ली कैपिटल रीजन में 17 साल का एक लड़का अपने पिता की स्कॉर्पियो एस.यू.वी. को लापरवाही और गलत तरीके से चला रहा था, उसकी बहन उसकी बगल में बैठी थी। बहन का काम था कि वह गाड़ी चलाते समय अपने भाई की रील बनाए।

वह अपने दोस्तों को इम्प्रैस करने के लिए यह रील अपने सोशल मीडिया अकाऊंट पर पोस्ट करता था। इससे पहले भी गाड़ी का कई बार ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन के लिए चालान कटा था, ज्यादातर तेज गाड़ी चलाने के लिए। पिता ने जाहिर है अपने बेटे की इन गलतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार पिता को ध्यान देना पड़ा क्योंकि लड़के ने सड़क की गलत साइड पर गाड़ी चलाई और सीधे एक आती हुई कैब और एक टू-व्हीलर को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पलट गई। इस वजह से साहिल नाम के 23 साल के लड़के की मौत ने एक न्यूज चैनल का ध्यान खींचा, जिसने एक वीडियो हासिल किया, जिसमें पूरा मामला दिखाया गया था और उसे सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाया। चैनल ने कसम खाई है कि जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अब समय आ गया है कि अधिकारी समझें कि सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल करने वाले आम लोग भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, जितने अमीर और ताकतवर लोग, जिन्हें गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं लगती। इस मामले में लड़के के पिता से पुलिस ने पूछताछ की और अनजान वकीलों की कानूनी सलाह पर उन्हें छोड़ दिया। और एक साथी इंसान की हत्या करने के बावजूद अपराधी को परीक्षा में बैठने दिया गया।-जूलियो रिबेरो (पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कनल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीयरवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/...)

रमज़ान का पहला जुमा: नमाज़ियों से गुलज़ार रहीं मस्जिदें

मुरादाबाद।

माहे मुबारक के पहले जुमे पर शहर की जामा मस्जिद समेत अन्य तमाम मस्जिदें नमाज़ियों से गुलज़ार रहीं। मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह से ही जुमे की नमाज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दीं थीं। बड़ी तादाद में लोग जुमे की नमाज़ अदा करने जामा मस्जिद पहुंचे। शहर की तमाम अन्य मस्जिदें भी नमाज़ियों से फुल रहीं। नमाज़ के दौरान उलेमाओं ने माहे मुबारक की फ़ज़ीलतें बयान फरमायीं। नमाज़ के बाद लोगों ने इफ्तार के सामान की खरीदारी की। रमज़ान मुबारक के पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद पहुंचे। ब'चों से लेकर बुजुर्गों तक में पहले जुमे

की नमाज को लेकर उत्साह देखने को मिला। यहां नायब शहर इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली ने नमाज़ अदा कराई। इससे पहले उन्होंने अपने खिताब में माहे मुबारक की फ़ज़ीलत बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि हमें इस माह 'यादा से 'यादा इबादत करनी चाहिए। गरीबों एवं ज़रूरतमंदों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए, इससे अल्लाह खुश होता है। लिहाज़ा इबादत में कोई कंजूसी न की जाये। बाद में सभी ने मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ की। इसके साथ ही मस्जिद जामिया नईमियां, मरकज़, लाल मस्जिद, किले वाली मस्जिद, कचहरी वाली मस्जिद, कुईयां वाली मस्जिद, तख्त वाली मस्जिद, इस्हाकी मस्जिद समेत शहर की सभी मस्जिदों में रोजेदारों

की काफी भीड़ रही। अस्र की नमाज के बाद इफ्तारी का सामान खरीदने वालों की बाजारों में भी भीड़ रही।

'कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें किसान'

मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद के ग्राम अब्बकरपुर में इफ्को एवं गन्ना विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किसान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद इफ्को उप क्षेत्र प्रबंधक यशवीर सिंह, गन्ना उप प्रबंधन निर्मल पंत, गन्ना पर्यवेक्षक प्रद्युम्न कुमार, एमडीई सुरेश मौर्या सहित 50 किसानों ने प्रति भाग लिया। यशवीर सिंह द्वारा किसानों को जल वायु एवं मिट्टी प्रदूषण से बचाव के लिए कम से कम रासायनिक खादों का खेतों में प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया नेनो, नैनो डीएपी जोकि पत्तियों पर प्रयोग की जाती है तथा नैनो डीएपी से बीज व जड़ , गन्ने की सेटे उपचार किये जाते है जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है आने वाली सीजन के लिए नैनो डीएपी से बीज उपचार करके बोने से जड़ का विकास, कल्ले विकास अधिक होता है इसके प्रयोग को आप लोग बढ़ावा दीजिए अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब हमारी फसल के लिए दानेदार उर्वरकों से अधिक लाभकारी नैनो उत्पाद रहेंगे। किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक नैनो,नैनो कॉपर, जैव उर्वरक, डिकंपोजर एवं सागरिका के महत्व के बारे में बताया गया साथ ही उसकी प्रयोग करने की विधि के विषय में बिस्तार में चर्चा की गई। इसी कड़ी में गन्ना विभाग से आये अधिकारियों द्वारा गन्ना उप प्रबंधक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत गन्ने की क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु और अ'छे उत्पादन हेतु समस्त जानकारी का आदान-प्रदान किया गया। गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा गोष्ठी आए सभी किसान साथियों का अंत में धन्यवाद करके गोष्ठी का समापन किया गया।

ताइक्कांडो कलर बेल्ट टेस्ट सफलतापूर्वक समापन

बिलारी। क्षेत्र के एसबीएस स्कूल में ताइक्कांडो का कलर बेल्ट टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया इस बेल्ट टेस्ट में नेशनल रेफरी प्रियांशु रस्तोगी एवं कामीया सैनी ने बतौर परीक्षक खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया। यह परीक्षा येलो, ग्रीन, ग्रीन वन, ब्लू, ब्लू वन तथा रेड बेल्ट के लिए आयोजित की गई। खिलाड़ियों ने तकनीकी कौशल के साथ-साथ पावर, स्पीड, फुर्ती (एजिलिटी), सहनशक्ति (एंड्यूरेंस) और टारगेट कंट्रोल तथा लकड़ी के फत्ते तोड़ कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ताइक्कांडो कोच सुमित शर्मा ने बताया कि ताइक्कांडो में ब्लैक बेल्ट एक डिग्री के समान होती है, जिसके बाद खिलाड़ी अपने खेल करियर को उ'च स्तर तक आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया कि एसबीएस स्कूल के खिलाड़ी अब ब्लैक बेल्ट से केवल रेड वन बेल्ट दूर हैं, जो उनके निरंतर परिश्रम और अनुशासन का परिणाम है। इस अवसर पर विद्यालय के खेल शिक्षक यशवीर सिंह और आशीष चौधरी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि यह बेल्ट टेस्ट प्रत्येक तीन माह में आयोजित किया जाता है, जिससे खिलाड़ियों की प्रगति और फिटनेस का निरंतर आकलन किया जा सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य संयोग वशिष्ठ ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एसबीएस स्कूल खेलों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने का सराहनीय कार्य कर रहा है।

भाकियू ने भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने पर दिया ज़ोर

मुरादाबाद।

भारतीय किसान यूनियन बलराज गुट की मुरादाबाद मंडल इकाई ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से देश के कृषि एवं उद्योग उत्पादों को बाहर रखे जाने एवं समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की मांग उठाई है। संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में मंडल अध्यक्ष नौशाद अली के नेतृत्व में शुक्रवार को एक ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर उप नगर मजिस्ट्रेट को पेश किया, जिसमें कहा गया है कि 13 फरवरी 2025 को भारत व अमेरिका के बीच पारस्परिक व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए दो दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तथा जब अमेरिका से तेल और व्यापार समझौते में भारत के कृषि व दुग्ध पदार्थों को शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है तो समझौता किए बिना देश वापस आ गए जिसकी संगठन सराहना करता है किंतु प्रधानमंत्री के आश्वासन के 1 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया कि अब भारत ने रूस से तेल लेने से मना कर दिया है तो अब ट्रेड डील का रास्ता खुल गया है भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ के बदले 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया गया और 25 प्रतिशत भी हटा दिए जाने की बात कही गई। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के किसानों को तब झटका लगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के फौरन बाद अमेरिका की कृषि सचिव का बयान आया कि इंडिया अमेरिका डील के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका के किसानों और पशुपालकों को बहुत फायदा होगाज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर किसान और पशुपालकों को इस ट्रेड डील से बाहर न रखा गया तो इस कृषि प्रधान देश के किसान ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हालात फिर से पैदा नहीं होने देंगे किसान देश को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष नौशाद अली ने बताया इस दौरान अजीम सैफी फरमान सैफी रिजवान चौधरी और मोहम्मद फैजान आदि मौजूद रहे।

युवाओं के लिए बड़ी समस्या है बेरोजगारी-अधिवक्ता

जाने अनजाने अपराधिक गतिविधियों में हो जाता संलिप्त राजनीतिक पार्टियों के मुखिया सिर्फ भाषणों में संवारते युवाओं का भविष्य

फतेहपुर।

रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कल भी युवा संघर्षरत था और आज भी है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका आज़ादी से लेकर आज तक राजनीतिक पार्टियां लाभ ले रही हैं। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनसे वोट लेती हैं और सत्ता में आने के बाद उनको भूल जाती हैं। जब सत्ता चली जाती है तो फिर युवाओं की याद आती है। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों व उनके प्रत्याशियों को चुनाव के समय युवाओं को भी भूल जाना चाहिए। अजय गोविन्द दुबे एडवोकेट, संगम सिंह एडवोकेट, प्रवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, शाहिद अख्तर एडवोकेट, फहीम खान एडवोकेट व मोहम्मद हफीज एडवोकेट ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ते अपराध के पीछे युवाओं का बड़ी संख्या में बेरोजगार होना है। राजनीतिक पार्टियों के मुखिया युवाओं के वोट लेने के लिए चुनाव के समय खूब भाषण देते हैं। परन्तु सरकार में आने के बाद युवाओं को भूल जाते हैं। युवाओं को चाहिए कि वह भी चुनाव के समय ऐसी पार्टियों के प्रत्याशियों की तरफ ध्यान न दें। कहा कि युवाओं के पास जब काम नहीं होता है तो उनको लोग गुमराह कर देते हैं। कुछ नशे के आदी हो जाते हैं और फिर कहीं न कहीं जाने अनजाने अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। इसका कारण युवाओं के हाथ में काम का न होना है। कहा कि राजनीतिक पार्टियों के मुखिया चुनाव के समय युवाओं से वोट लेने के लिए उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद भूल जाते हैं। जब सरकार चली जाती है तो उन पार्टियों के मुखियाओं को फिर युवाओं की याद आती है। ऐसी पार्टियों के मुखिया व प्रत्याशियों से युवाओं को दूर ही रहना चाहिए।

पकरी सेवार सड़क जर्जर, गंगा स्नानार्थी गिरकर घायल , गड्ढों और बिखरी गिट्टियों से आवागमन में परेशानी

मेजा, प्रयागराज ।

तहसील क्षेत्र के गंगा तट पर स्थित पकरी सेवार गांव की मुख्य सड़क इन दिनों जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और बिखरी गिट्टियां राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब पखवाड़े भर पहले लोक निर्माण विभाग ने कुछ गड्ढों में गिट्टी डलवाई थी, लेकिन उस पर पिचिंग नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप सड़क पर गिट्टियां बिखर गईं, जो अब राहगीरों के फिसलकर गिरने का कारण बन रही हैं।गांव के धीरज यादव ने बताया कि प्रतिदिन तड़के चार बजे डोहरिया, जयराम का पुरा और परानीपुर सहित विभिन्न गांवों के श्रद्धालु इसी मार्ग से गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीण आनंद कुमार, कृष्ण प्रकाश द्विवेदी और ललन तिवारी के अनुसार, गंगा तट पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर के समीप करोड़ों रुपये की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। दक्षिण भारत की संस्था गजा द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन बिछाने से गांव की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान जल निगम की पाइपलाइन और प्राथमिक विद्यालय तक गई इंटरनेट केबल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संबंध में जल जीवन मिशन के अवर अभियंता अखिल देव सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण में आने वाले खर्च का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग से मांगा गया है। प्रस्ताव मिलते ही बजट जारी कर दिया जाएगा और सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा।ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और गंगा स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन मिल सके।

नमो भारत का बढ़ा दायरा, सराय काले खां और बेगमपुल तक दौड़ेगी हाईस्पीड रेल; पीएम करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली अभी तक दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक पहुंच रही नमो भारत रेल अगले तीन दिनों में सराय काले खां तक पहुंचने लगेगी। इससे यात्रियों की नमो रेल के साथ भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो और बस तक सीधी पहुंच होगी। आज यानी शुक्रवार को इस ट्रेन का ट्रायल रन होगा जबकि प्रधानमंत्री मोदी दो दिन बाद 22 फरवरी को दोनों कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही आम लोग के लिए कॉरिडोर खोल दिया जाएगा जिससे सराय काले खां मेगा ट्रांसपोर्ट हब से यात्री अपनी मंजिल के लिए आसानी से दूसरा वाहन पकड़ सकेंगे। मेरठ साउथ नमो स्टेशन से आगे बेगमपुल स्टेशन तक जाना भी संभव होगा। दरअसल, दिल्ली-मेरठ नमो कारीडोर का न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ नमो स्टेशन का करीब 55 किमी लंबा हिस्सा चालू है। शेष सेक्शन इससे जुड़ने वाले हैं। इसमें दिल्ली की तरफ सराय काले खां से न्यू अशोक नगर का करीब पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा अब तैयार हुआ है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम का 21 किमी का स्ट्रेच भी पूरा है। दोनों हिस्सों को आवाजाही के लिए शुरू किया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार पहली बार नमो रेल सरायकाले खां से बेगमपुल तक चलेगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीडियाकर्मी भी शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि मेरठ मेट्रो का काम भी पूरा हो गया है। 23 किमी लंबी इस मेट्रो में 13 स्टेशन हैं। इस कारीडोर का भी 22 फरवरी को उद्घाटन होगा। इससे मेरठ के भीतर और मेरठ से नमो रेल तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। यात्रियों को निजी वाहनों से नमो स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। दिल्ली मेट्रो का मजलिस पार्क-मौजपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क सेक्शन तैयार है। फेज-4 के तहत बने दोनों सेक्शन पर ट्रायल रन भी पूरा होने के साथ कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने भी मेट्रो चलाने की अनुमति दे दी है। इनका उद्घाटन भी 22 फरवरी को होगा। दोनों कॉरिडोर की लंबाई करीब 23 किमी है। इसमें मजलिस पार्क-मौजपुर लाइन के करीब 13 किमी में आठ स्टेशन हैं। दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर के जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर का हिस्सा है। यह मजेंटा लाइन का विस्तार है। मजेंटा लाइन अभी बोटेनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक चल रही है। कृष्णा पार्क से दीपाली चौक तक निर्माण कार्य जारी है। वहीं, दीपाली चौक से मजलिस पार्क करीब दस किमी लंबा हिस्सा तैयार है।

दोनों कारीडोर उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। करीब दो किमी लंबा एरोसिटी से आईजीआई टी-1, करीब चार किमी लंबा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और करीब दस किमी लंबा रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ मेट्रो कारीडोर का शिलान्यास भी हो सकता है। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने इन तीनों कॉरिडोर को कैबिनेट से मंजूरी दी थी।"

इंडिया एआई समिट की बड़ी कामयाबी- होगा 250 अरब डॉलर का निवेश, 70 से अधिक देश घोषणापत्र पर करेंगे हस्ताक्षर

नई दिल्ली !

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोजन को एक बड़ी सफलता करार दिया है। इस वैश्विक महासम्मेलन में न केवल बुनियादी ढांचे के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हासिल हुआ है, बल्कि 70 देशों ने भारत के कूटनीतिक नेतृत्व में दिल्ली घोषणापत्र पर अपनी सहमति भी जता दी है। आसान शब्दों में कहें तो, यह समिट भारत को तकनीक की दुनिया में एक नए ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है।

दिल्ली घोषणापत्र पर दुनिया का साथ

इस शिखर सम्मेलन का सबसे अहम कूटनीतिक हिस्सा दिल्ली घोषणापत्र रहा है। शुक्रवार को 20 फरवरी 2026 को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अब तक 70 देश इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और कई अन्य देशों के साथ बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शनिवार को इस आयोजन के समापन तक सहमति जताने वाले देशों का अंतिम आंकड़ा 80 को पार कर जाएगा। इस दिल्ली घोषणापत्र की विस्तृत रूपरेखा और इसके अहम बिंदुओं को शनिवार को पूरी पारदर्शिता के साथ दुनिया के सामने साझा किया जाएगा।

निवेश का अंबार और जनता की भारी भागीदारी

भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत को घरेलू स्तर पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आईटी मंत्री ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पांच से अधिक आगंतुकों ने हिस्सा लिया, जो देश में उभरती तकनीक के प्रति भारी उत्साह को दर्शाता है। इसके अलावा, इस आयोजन के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश कमिटमेंट प्राप्त हुए हैं।

यह भारी-भरकम निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा।

विपक्ष का विरोध और युवाओं का करारा जवाब

इस बड़े तकनीकी आयोजन के बीच कुछ राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को बाधित करने के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए आईटी मंत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल के इस छोटे से प्रयास को देश के युवाओं ने मजबूती से और पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

बुनियादी ढांचा- 250 अरब डॉलर के निवेश कमिटमेंट से देश के टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

वैश्विक कूटनीति- दिल्ली घोषणापत्र पर 70 से अधिक देशों का एक साथ आना यह प्रमाणित करता है कि अंतरराष्ट्रीय एआई नीतियों को तय करने में भारत एक अहम कूटनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। इंडिया एआई समिट ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

5 लाख आगंतुकों की भागीदारी और 250 अरब डॉलर का भारी निवेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। शनिवार को जब दिल्ली घोषणापत्र के विस्तृत विवरण दुनिया के सामने आएंगे, तो भविष्य की तकनीकी नीतियों की तस्वीर और भी साफ हो जाएगी।

देश से जो गद्दारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा: मनोज सिन्हा

जम्मू उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी दी है कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की गंभीरता से जांच करेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ घर वापसी को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि कश्मीरी पंडितों की पूरी इज्जत और सुरक्षा के साथ वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है। उन्होंने कहा, अपनी धरती पर अजनबी बन जाना दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ घर वापसी को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि कश्मीर पंडितों की पूरी इज्जत और सुरक्षा के साथ वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है। एलजी प्रो. अशोक कौल की किताब कश्मीर-नेटिविटी रीगेंड के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। जम्मू विश्वविद्यालय के एनेंद्र सिंह सभागार में हुए कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा कि अपनी धरती पर अजनबी बन जाना दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक है। अपनी जड़ों से उजड़ जाने का दर्द आज भी बेघर हुए परिवारों की रगों में कांटों की तरह चुभता है। समय का मरहम भी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का गहरा दर्द नहीं भर सका। एलजी ने कहा कि युवा पीढ़ी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हजारों निर्दोष कश्मीरी मुसलमानों का भी खून बहाया है। कई मामले इतने हृदयविदारक होते हैं कि उन्हें दोहराते समय शब्द लड़खड़ा जाते हैं। पिछले साल से उन परिवारों को न्याय मिलना शुरू हो गया है और अन्य आवश्यक चीजों के साथ-साथ उनकी रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास चल रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह भरोसा पैदा हुआ कि कश्मीरी पंडित समुदाय की युवा पीढ़ी बिना किसी डर के अपनी जड़ों की ओर फिर से लौट सकती है। समारोह में डीन रिसर्च स्टडीज जम्मू यूनिवर्सिटी डॉ. नीरज शर्मा, मंडलायुक्त रमेश कुमार, आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी सहित कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य मौजूद थे। जम्मू विश्वविद्यालय के बजेंद्र सिंह सभागार में पुस्तक विमोचन समारोह में मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय की जबरदस्त भावना को मैं सलाम करता हूं।

सीएम योगी ने ली चुटकी, बोले- माता प्रसाद पांडेय को न लगे शिवपाल यादव का श्राप

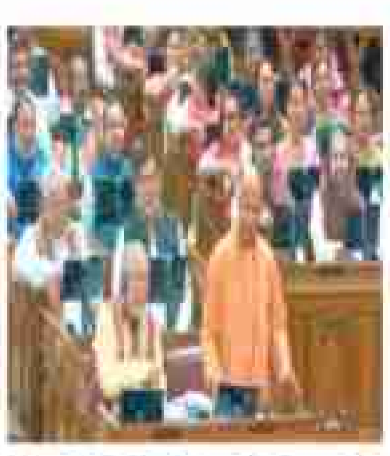

लखनऊ सदन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष ने सार्थक चर्चा की। इसके लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद, कि उन्होंने सदन में भाग लिया। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को शिवपाल यादव का श्राप न लगे, वह स्वस्थ रहें। सीएम ने कहा कि राजकोषीय घाटे की बात का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष पर चच्चू (शिवपाल यादव) का असर आ गया है। 2016-17 में ऋण ग्रस्तता लगभग 30 फीसदी थी। हमने इसे 27 फीसदी किया। आगे इसे 23 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य है। बजट सत्र में प्रदेश में कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि आज प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा का कर्ज है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विरोध जताया। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि इतना कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अंगुली उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में तो छोड़ो, मेडिकल कॉलेज तक में रेफर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जीवन-मरण से संबंधित है, इसलिए इस विभाग में संविदा में कर्मी नहीं रखे जाएं। आज एक हजार पर 0.37 डॉक्टर है, जबकि डब्लूएचओ का मानक है एक हजार पर 1 डॉक्टर हो। सरकार अभी तक इस मानक तक नहीं पहुंची है। शिक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर कानून बनाकर रोक लगनी चाहिए। गलगोटिया पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो लोग बहुत फीस लेते हैं। आजकल गलगोटिया अपना कुत्ता खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि इसे हमने बनाया है। एक समय में इलाहाबाद विवि एक समय अधिकारी बनाने का कारखाना थी। लेकिन, पढ़ाई की गुणवत्ता आज काफी खराब हो गई है। विश्व विद्यालयों में गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है। गंगा मैया आज गंदगी से बिलख रही है। इसकी सफाई पर भी सरकार ध्यान दे। बजट पर चर्चा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने संसदीय कार्य मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम लोग कोई कार्य लेकर आएं तो प्रमुखता से सुनें। बजट के लिए 9 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि आवंटित हुई है, तो यह बजट व्यय भी हो। जो भी प्रस्ताव मिले, आप उसे पास करें। उन्होंने पेयजल की समस्या भी उठाई। कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जब तक सभी जगहों पर पानी की टंकियां शुरू नहीं हो जातीं, तब तक हैंडपंप रिबोर की व्यवस्था बनाए रखें।

सीएम योगी की बड़ी घोषणा- शिक्षामित्रों को 10 की जगह 18 हजार रुपये हर महीने मिलेंगे, अनुदेशकों को 17 हजार

लखनऊ !

प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षामित्रों को अब 10 हजार की जगह 18 हजार और अनुदेशकों को नौ हजार की जगह 17 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। यह मानदेय अप्रैल माह से भुगतान किया जाएगा। इससे करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और करीब 25 हजार अनुदेशक लाभान्वित होंगे। इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को तीसरी बड़ी घोषणा की। इससे पहले वह विधान परिषद में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं तो विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। शुक्रवार को वह करीब दो घंटे 50 मिनट के वक्तव्य में सर्वाधिक समय शिक्षा व्यवस्था पर दिया। सुधार की चर्चा करते हुए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की।

यह भी बताया कि सभी शिक्षकों को पांच लाख तक के कैशलेस चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। बजट पर वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर तंज भी कसा। कहा कि सपा सरकार इन्हीं शिक्षामित्रों को सिर्फ तीन हजार मानदेय देती थी। उन्होंने उच्च शिक्षा का जिक्र करते हुए प्रेशिंग सुधार, विदेश जाने के लिए स्कालरशिप योजना, स्टार्टअप सहित अन्य योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में दो इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। पहला लखनऊ और उससे सटे जिलों बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई जिले को जोड़कर बनाया जाएगा। दूसरा वाराणसी और उससे सटे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र को जोड़कर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी को प्रदेश का सुप्रीम रेगुलेटर और आर्किटेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अथॉरिटी विभिन्न विभागों से डाटा एकत्रित कर उसे एकीकृत करेगी। उसका विश्लेषण करेगी और नीति निर्माण में उसका उपयोग सुनिश्चित करेगी। यह डाटा को जोड़ने और उसका सार्थक उपयोग करने में क्रिटिकल थिंकिंग हो वास्तविक गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने एआई की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए, कहा कि युवाओं को एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने की सुविधा देंगे। प्रदेश सरकार 25 लाख युवाओं को यह यह सुविधा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विभाग 15 मई तक प्रस्ताव दे दें। ताकि समय से बजट जारी किया जा सके और कार्य भी समय से पूरा हो सके।

पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- अदृश्य राजनीतिक दबाव में हैं प्रधानमंत्री

नई दिल्ली ! राहुल गांधी ने संसद में इस्तेमाल किए गए अपने जिउ-जित्सु के उदाहरण को समझाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक पकड़ और दबाव में फंसे हुए हैं, जो जनता को दिखाई नहीं देते। x पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने संसद में अपने भाषण में जिउ-जित्सु का उदाहरण क्यों दिया। मैंने पकड़ और दबाव का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जिउ-जित्सु खेल में होते हैं और इसी तरह प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में भी इसी तरह के तरीके मौजूद हैं, लेकिन जनता को दिखाई नहीं देते। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राजनीतिक पकड़ और दबाव ज्यादातर छिपे रहते हैं। आम आदमी उन्हें देख नहीं पाता। और यह देखने के लिए कि दबाव कहां लगाया जा रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा। गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दबावों के बीच फंसे हुए हैं। अमेरिका में अडानी मामले और एपस्टीन मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कई भारतीय नाम उन फाइलों से जुड़े हैं जिन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है। गांधी ने कहा कि एक तरफ चीन हमारी सीमा पर बैठा है, और दूसरी तरफ अमेरिका। और हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच फंसे हुए हैं। वे फंसे हुए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि वित्तीय समर्थन से कायम है और उस छवि पर नियंत्रण भारत के बाहर के लोगों के हाथों में है। गांधी ने दावा किया कि नीतिगत फैसलों का असर किसानों और कपड़ा क्षेत्र पर पड़ सकता है, और आरोप लगाया कि भारत को अमेरिका से आयात बढ़ाना पड़ सकता है। उन्होंने डेटा प्रबंधन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। तथ्य यह है कि हमारा डेटा नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की अमेरिकी कंपनियों को मामूली कीमत पर सौंपा जा रहा है। और मेरी बात याद रखिए, हम डेटा कॉलोनी बनने जा रहे हैं। गांधी ने सवाल उठाया कि भारत अमेरिका के साथ डेटा, कृषि और उद्योग से संबंधित समझौते क्यों करेगा, और कहा कि इसका जवाब प्रधानमंत्री पर लगाए गए दबाव और दबाव में निहित है।

प्रियंका गांधी सीएम हिमंत पर हमलावर

सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें, गौरव गोगोई का किया बचाव

गुवाहाटी । कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को असम के गुवाहाटी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे राज्य के विकास और युवाओं को रोजगार देने के बजाय निजी हमलों में उलझे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि शासन और विकास पर ध्यान देने की जगह मुख्यमंत्री का पूरा जोर विरोधियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर है। सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध होने के गंभीर आरोपों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने सीएम सरमा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों के सहारे किसी के परिवार और बच्चों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। प्रियंका ने कहा, 'झूठ फैलाकर किसी के परिवार पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है।

इसके बजाय मुख्यमंत्री को असम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आज असम के युवाओं को नौकरियों और रोजगार के मौकों की सख्त जरूरत है।' उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि असम की जनता गौरव गोगोई पर मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए ऐसे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। प्रियंका ने गौरव गोगोई का बचाव करते हुए उन्हें एक सकारात्मक नेता बताया जो मूल्यों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग से जुड़े विवाद पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि कलाकारों को सियासी लड़ाई से दूर रखा जाए। उन्होंने जुबीन गर्ग को राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक बताते हुए कहा, जुबीन गर्ग असम की आत्मा हैं। वह एक ऐसे इंसान हैं जो राजनीति से ऊपर हैं।

उन पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात करेगी। उनका पूरा जोर बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और विकास जैसे विषयों पर रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मूल्यों और जनता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का लक्ष्य लोगों पर केंद्रित शासन देना है।

असम को बड़ी सौगात- 14 मार्च को बराक घाटी आएंगे पीएम मोदी, 22,000 करोड़ के गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे की रखेंगे नींव

नई दिल्ली ! असम में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बराक घाटी के विकास के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। शुक्रवार को सिलचर में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 मार्च को बराक घाटी का दौरा करेंगे और राज्य के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और 22,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। शर्मा ने सिलचर में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से गुवाहाटी और सिलचर के बीच का सफर मौजूदा आठ घंटे से घटकर साढ़े चार घंटे का रह जाएगा। शर्मा ने बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण का कार्य भी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है और सड़क निर्माण जल्द ही शुरू होगा। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान सिलचर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। असम में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सिलचर में प्रस्तावित 'ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को कुम्भीरग्राम के इसके लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी की जरूरत होगी.. समय कम बचा है लेकिन हम मार्च तक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर यह संभव नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव के बाद होगा। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है।

एआई समिट में प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ता गिरफ्तार

दिल्ली ! भारत मंडपम में चल रही इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शुक्रवार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे आयोजन स्थल पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। हंगामा जिस वक्त खड़ा हुआ, उस वक्त भारत मंडपम में विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने कपड़े उतारकर पीएम इज कंप्रोमाइज के नारे लगा रहे थे। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। बेहद सुरक्षित इलाके में हंगामा खड़ा करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, दूसरों की पहचान की जा रही है। इससे पहले दोपहर बाद करीब 12:30 बजे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्यूआर कोड से एआई समिट में प्रवेश किया। वह हॉल नंबर-5 के लॉबी एरिया में पहुंचे। इसे बाद स्वेटर व जैकेट उतारकर वह प्रदर्शन करने लगे। उनकी टी शर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थी, जिस पर इंडिया यूएस ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल्स और पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। अचानक शुरू हुए हंगामे आयोजन स्थल पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों को हाथ-पांव फूल गए। सरकारी अधिकारियों, इंडस्ट्री के नेताओं और विदेशी डेलीगेट्स की भागीदारी वाले इस हाई-प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट में इस तरह के प्रदर्शन से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लिया गया और जगह से दूर ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाकी की पुलिस पहचान कर रही है।

चुप नहीं बैठेंगे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता

इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि एआई समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के साथियों ने स्पष्ट कर

दिया कि देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। पीएम के खिलाफ लगाया गया नारा सिर्फ एक नारा नहीं, करोड़ों बेरोजगार युवाओं का आक्रोश है। अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील हमारे किसानों और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। इससे सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार है और हम युवाओं की आवाज बुलंद करते रहेंगे। उदय भानु चिब ने यह भी कहा कि वह एआई समिट के खिलाफ नहीं है। हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ है। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हों, युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या हम खामोश रहें? यह देश 140 करोड़ नागरिकों का है।

यूथ कांग्रेस का हंगामा देश की छवि खराब करने की कोशिश- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि जब भारत के युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तकनीकी प्रगति का संदेश दुनिया को दिया जा रहा था, तब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यह कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और हताशा का परिणाम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती ताकत से विचलित है और इसी कारण ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। ऐसे मंच को बाधित करना राष्ट्रहित के विरुद्ध है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि भारत मंडपम में जारी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट भविष्य की दिशा तय कर रहा है।

कांग्रेस की तरफ से किया तमाशा बेहद शर्मनाक है। जब भी देश अपनी सामर्थ्य दिखाता है या कोई वैश्विक आयोजन होता है तो कांग्रेस को जैसे मरोड़ उठने लगती है और वह बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। सीएम ने कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने जो हुड़दंग मचाया गया, भारत की साख बिगाड़ने का वह सुनियोजित षड्यंत्र है। राहुल गांधी का नकारात्मक नेतृत्व एक सोची-समझी रणनीति के तहत देश की छवि धूमिल करने पर उतारू देता है। इससे हर वह भारतीय शर्मिंदा है, जो देश की प्रगति पर गर्व करता है।